कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

महासंग्राम रैली, भुवनेश्वर (ओडिशा)

'मेक-इन-इण्डिया' नीति से लाभ उठाकर देश को प्रगति मार्ग पर ले जाएं. 6

भाजपा अध्यक्ष का प्रवास

महाराष्ट्र........ 10
कर्नाटक........ 10

लेख

अमित शाह दोषमुक्त
– **अरुण जेटली**........ 12
दिल्ली में भाजपा को मिल सकता है पूर्ण बहुमत
– **संजीव कुमार सिन्हा**........ 16
देश भर में भाजपा के 1058 विधायक और कांग्रेस के 949
– **राम नयन सिंह**........ 21

अटलजी का प्रथम अध्यक्षीय भाषण

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा........ 23

अन्य

प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा........ 9
102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस........ 15
भाजपा बिहार प्रदेश कार्यसमिति बैठक........ 18
दिल्ली भाजपा की कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न........ 20
दो दिवसीय नवनिर्वाचित विधायक प्रशिक्षण शिविर........ 26
योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना........ 27
झारखंड : दसवें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास ने शपथ ली........ 28
भाजपा, अजा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक........ 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को

मकर संक्रांति

व

गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं!

शिक्षा का सदुपयोग

आयुर्वेद के एक विख्यात वैद्य थे नागार्जुन। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से शिष्य आते रहते थे। एक दिन दो शिष्य उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनकी योग्यता परखने के लिए आचार्य ने उनसे कहा कि तुम पहाड़ पर जाओ और वहां से बुखार और दर्दनाशक बूटी लेकर आओ। दवा की पहचान आचार्य ने दोनों को बता दी। शिष्य पहाड़ की ओर चल दिए। शाम को जब दोनों शिष्य अपनी अपनी दवा की बूटी लेकर वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति बुखार से परेशान नजर आया।

दोनों शिष्य उसके पास गए और बोले- 'आपको क्या तकलीफ है?' उसने कहा- 'मुझे दो रोज से तेज बुखार है, पर पैसा न होने के कारण मैं वैद्य के पास नहीं जा पाया।' तभी एक शिष्य ने अपनी बुखार की बूटी उसे दे दी। दूसरा शिष्य अपने साथी पर बहुत नाराज हुआ और बोला- 'तुम आचार्य के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो।' कुछ दूरी पर उन्हें एक बच्चा रोता दिखाई दिया। बच्चे के पैर में चोट लगी थी, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। दूसरे शिष्य के पास दर्दनाशक की बूटी थी, पर उसने नहीं दी। बच्चे को बिलखता छोड़ वे आगे बढ़ गए। शाम होते-होते दोनों आचार्य के पास पहुंचे। दूसरे शिष्य ने आचार्य को दर्द की दवा सौंप दी, पर पहला शिष्य खाली हाथ खड़ा था। उसने आचार्य को पूरी घटना सुना दी।

उसकी बात सुनकर आचार्य ने कहा- 'कोई भी शिक्षा तभी फलदायक होती है, जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो।' दूसरे शिष्य को वहां प्रवेश नहीं मिला।

संकलन : मिलन सिंह
(नवभारत टाइम्स)

पाथेय

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्त्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्त्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरंतर गतिशील फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भाँति निरंतर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएँ रखती हैं जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करनेवाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति शास्त्र, समाज रचना इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग अंगों में व्यक्त होती हैं।

- दीनदयाल उपाध्याय (पांचजन्य, भाद्रपद कृष्ण 9, वि.सं. 2006)

नीति आयोग से होगा क्रांतिकारी बदलाव

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) का गठन हो चुका है। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। इससे नीति-निर्धारण में न केवल क्रांतिकारी बदलाव होगा, बल्कि लोगों की नई आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य-योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। आज भारत तेजी से उभरता हुआ विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए इसे ऐसे वैश्विक दृष्टि व पहल की जरूरत है जिससे भारत का स्थान विश्व के अग्रणी देशों में सुनिश्चित हो सके। नीति आयोग इस दिशा में एक उचित पहल है। इससे उच्चस्तर की विशेषज्ञता, प्रवर्तनशील पद्धतियां व नए दृष्टिकोण का समावेश होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग की जगह इस नई संस्था के निर्माण की घोषणा की। इस घोषणा का देश के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया। यह एक महान सुधारात्मक कदम है। इससे देश के समक्ष नई चुनौतियों से निपटने में सरकारी योजनाओं को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। योजना आयोग एक पुरानी संस्था है जिसकी उपयोगिता पर प्रश्न उठते रहे थे। योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के एक संकल्प द्वारा किया गया था। इसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना तथा तद्नुरूप राज्यों को फंड वितरित करना था। इसका निर्माण सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। हालांकि योजना आयोग से उम्मीद थी कि इससे देश के विकास में मदद मिलेगी, लेकिन यह लालफीताशाही व अति केंद्रिक प्रवृत्तियों का शिकार हो गई। इस पर प्राय: अतिकेंद्रितकृत और फंडों के वितरण पर राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलती चुनौतियों के सामने योजना आयोग अपनी प्रासंगिकता साबित करने में असमर्थ साबित हो रहा था। साथ ही यह लोगों की नई आकांक्षाओं व देश के संघीय ढांचें में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया।

अतिकेंद्रिकृत योजना आयोग के बदले नीति आयोग सहयोगात्मक संघीय ढांचे के सिद्धांत पर कार्य करेगा। यह राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने व क्रियान्वयित करने का अवसर देगा। इससे अलावा यह लोगों की सहभागिता, अवसर की समान उपलब्धता, सहभागी व सहयोगात्मक शासन तथा तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रेरित करेगा। आज भारत तेजी से उभरता हुआ देश है। इसे वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते विभिन्न तकनीकी व सामरिक बदलावों में अपना अग्रणी स्थान सुनिश्चित करना है। डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना क्रांति के वैश्विक युग में एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो अपने अभिनव क्षमताओं व पहलों से बदलते परिवेश के साथ कदम मिला सके और विकास प्रक्रिया को सहयोगात्मक व सहभागी बना सके। ऐसे परिवेश में नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और सरकार के नीति-निर्माण में निर्देशात्मक पहल करेगा। सरकार नीति आयोग से एक संस्था के रूप में यह उम्मीद करती है कि यह केंद्र व राज्य सरकारों के बीच नीति-निर्धारण, विभिन्न विषयों पर उचित सामरिक व तकनीकी सुझाव और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विषयों पर सलाह देगी। यह संस्था अपने देश व विदेशों में प्रचलित अच्छे विचारों, नीतियों व कार्यक्रमों को देश में फैलाने में मदद करेगी।

देश नेहरू के आर्थिक मॉडल से आगे जा चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश में इसे अपना स्थान सुदृढ़ करना है। योजना आयोग नेहरू के आर्थिक मॉडल की उपज था और विशेषज्ञों ने इसकी प्रासंगिकता पर सदैव संदेह किया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन न केवल एक साहसिक कदम है, बल्कि इससे आर्थिक नीति-निर्माण व क्रियान्वयन में भारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ताकि देश नीति आयोग जैसी समर्थ संस्था के सहयोग से तीव्र आर्थिक विकास के युग में प्रवेश कर सके। ■

महासंग्राम रैली, भुवनेश्वर (ओडिशा)

केन्द्र सरकार की 'मेक-इन-इण्डिया' नीति से लाभ उठाकर देश को प्रगति मार्ग पर ले जाएं

हमारे संवाददाता द्वारा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केन्द्र में पिछली कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उसने देश को कई वर्ष पीछे धकेल दिया है।

6 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित महासंग्राम रैली में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कांग्रेस पर प्रहार जारी रखते हुए 31 दिसम्बर को पाकिस्तान नाव पर दखलंदाजी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या विपक्षी पार्टी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही है?

श्री शाह ने कहा कि ''मुझे लगता है कांग्रेस को मालूम नहीं है कि उनको चुनाव पाकिस्तान में लड़ना है या हिन्दुस्तान में। राहुल बाबा हमसे रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि हमने पिछले छह महीनों में क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में पिछले 60 वर्षों के अपने खानदानी शासन में आपके परिवार ने क्या किया?''

श्री शाह ने गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी ने उनके छह महीने के शासन का हिसाब मांगने से पहले कांग्रेस को देश को 60 वर्षों के अपने शासन का हिसाब देना चाहिए।

श्री शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से अपने प्रवक्ताओं से संवेदनशील मामलों पर बेकार की टिप्पणियां करने से बाज आने को कहा और बताया कि यह प्रमुख विपक्षी दल का दायित्व होता है कि वह सरकार की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के प्रयास में संदेह खड़ा करने की बजाए सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रोत्साहित करना उसका दायित्व बनता है।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की दोषपूर्ण नीतियों ने देश को मुद्रास्फीति और ऊंची कीमतों के गड्ढ़े में डाल दिया है और कहा कि भाजपा सरकार के छह महीने के शासन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाया गया है।

अरब सागर में सुरक्षा बलों के आप्रेशन पर सवाल खड़ा करने पर प्रहार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है कि

वह सुरक्षा बलों के मनोबल को ऊंचा उठाए न कि एनडीए सरकार के आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर गलतियां ढूंढ़े। मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि क्या वह भारत में चुनाव लड़ रही है या पाकिस्तान में?''

भाजपा अध्यक्ष ने जलमार्ग के रास्ते एक और आतंकवादी हमला रोकने के लिए तटवर्ती गार्डो तथा सुरक्षा खुफिया विंग की सराहना की। यह उल्लेखनीय है कि नववर्ष की रात्रि को एक समुद्री आप्रेशन में एक संदिग्ध पाकिस्तानी मछुआरा नाव को अरब सागर में तटवर्ती गार्डो ने विस्फोटक ले जाते हुए पकड़ा था, परन्तु उसमें आग लग गई और विस्फोट हो गया जिसमें उसके सभी चार कर्मीदल मारे गए।

यह कहते हुए कि लगभग 350 लोग मारे गए थे, जब 2009 में मुम्बई के निकट तटों पर पाकिस्तानी आतंकवादी उतरे थे और नगर पर हमला शुरू कर दिया था, परन्तु मोदी सरकार केन्द्र में शासन करते हुए इन हमलों को रोकने का संकल्प किए हुए है। उन्होंने कहा कि वे (पाकिस्तानी) सीमा पार से गोलियां चला रहे हैं, परन्तु एनडीए के शासन में चल रही सरकार ने भारत के जवाब में परिवर्तन लाया है और हम उन्हें कड़ा जवाब दे रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान पहले गोलियां चलाना शुरू करता था और बंद भी वही करता था। परन्तु, अब हम गोलियां चलाना बंद करते हैं।

श्री शाह ने राज्य में घोटालों पर टिप्पणी देते हुए कहा कि हालांकि ओडिशा में गरीबी है। परन्तु यह अपने संसाधनों में समृद्ध है अब केन्द्र की नई खनन नीलामी नीति से ओडिशा तथा झारखण्ड जैसे राज्यों को लाभ होगा, जिससे नीलामी से होने वाले लाभों से राज्य सरकार गरीबों के कल्याण पर पैसा खर्च कर सकेगी।

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि ओड़िशा के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। फिर भी यह राज्य अल्पविकसित रह गया है और ओड़िशा

देश में नम्बर एक राज्य बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओड़िशा तथा झारखण्ड जैसे पूर्वी राज्यों के समृद्ध संसाधनों के विकास को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

श्री शाह ने मोदी सरकार की 'मेक इन इण्डिया' नीति से लोगों को इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाने का आह्वान किया क्योंकि इनसे आने वाले दिनों में देश में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की भी सराहना की जिससे देश में 'वित्तीय अस्पृश्यता समाप्त होगी।

अन्य लोगों के अलावा केन्द्रीय आदिवासी मंत्री श्री जुआल आरोम, केन्द्रीय, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, ओड़िशा राज्य अध्यक्ष श्री के.वी. सिंह देव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखें।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओड़िशा से सक्रिय सदस्य बने

श्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से ओड़िशा राज्य से सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। एक विशेष सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन धौली में हुआ। श्री शाह ने 129 प्राथमिक सदस्य बनाए और उनकी सक्रिय सदस्यता की पुष्टि की। नि:संदेह, यह राज्य के लिए एक स्वर्णिम अवसर और परम गर्व की बात है।

अपने भाषण में श्री शाह ने लोगों से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 नवम्बर 2014 को नई दिल्ली में सदस्यता अभियान चलाया। कोई भी प्राथमिक सदस्य अन्य सौ सदस्य बना कर सक्रिय सदस्य बन सकता है। केवल सक्रिय सदस्यों को ही संगठनात्मक दायित्व दिए जाएंगे और वे पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर सकेंगे। अत: उन्होंने पार्टी के प्रत्येक सक्रिय सदस्य बनने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि मैं धौली जैसे एक ऐतिहासिक स्थान में सक्रिय सदस्य बना हूं।

श्री शाह ने गांवों में लोगों को जाने के लिए कहा और राज्य में 40 लाख सदस्यता का लक्ष्य पूरा करने के लिए

जोर-शोर से प्रचार करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सुशासन और विकास के मार्ग पर देश को ले जाने का संदेश दिया है। अत: हम ओड़िशा के लोगों की इस यात्रा में साथ चलना होगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें राज्य का विकास करना होगा और अपनी सेवाओं से गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभान्वित करना है। श्री शाह ने यह भी आशा व्यक्त की कि देश में ओड़िशा 'नम्बर वन' राज्य बनेगा और चहुं दिशा का विकास केवल भाजपा के सत्ता में आने से ही होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें राज्य में भाजपा संगठन को मजबूत करना होगा।

जैसा कि मुझे आज बताया गया है कि राज्य में कल तक 56 हजार प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने उन 129 प्राथमिक सदस्यों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने मुझे ऐसे स्थान से सक्रिय सदस्य बनाया है, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है।

श्री के.वी. सिंह देव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने श्री अमित शाह द्वारा ओड़िशा से सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने पर आभार प्रकट किया। उन्होंने निर्धारित समय में 40 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद जताई और केन्द्र में भाजपा शासन और भविष्य में राज्य में शासन का उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जताई।

इस अवसर पर श्री शिव प्रकाशजी, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, केन्द्रीय मंत्री श्री जुआल ओराम, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री अरूण सिंह, राष्ट्रीय सचिव और राज्य-प्रभारी, श्री प्रताप सडंगी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूरमा पाढ़ी, पूर्व मंत्री पृथ्वीराज हरीचंदन, समीर मोहंती, प्रवक्ता, भृगु बक्शी पात्र, प्रदेश सचिव, अभिया दास जिला प्रधान, भुवनेश्वर और दिलीप मोहंती आदि उपस्थित थे।

शेष पृष्ठ 19 पर

अमित शाह आरोप मुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को विशेष सीबीआइ अदालत ने 30 दिसंबर को फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश श्री एमबी गोसावी ने श्री शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर पूरी तरह गौर करने के बाद उसके आरोपों से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए आवेदक को बरी किया जाता है। श्री अमित शाह ने विशेष सीबीआइ अदालत में स्वयं को इस मामले से बरी करने का आग्रह करते हुए तर्क दिया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मामलों की सुनवाई अहमदाबाद से मुंबई हस्तांतरित कर दी गई थी। दोनों मामलों में श्री शाह सहित डीजी वंजारा एवं राजकुमार पांडियन जैसे कुछ पुलिस अधिकारियों को जमानत भी मिल गई थी।

क्या है मामला:

लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखनेवाले सोहराबुद्दीन का नवंबर, 2005 और उसके एक साथी तुलसी प्रजापति का दिसंबर, 2006 में गुजरात में एनकाउंटर कर दिया गया था। सीबीआइ ने श्री अमित शाह एवं कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों सहित कुल 37 लोगों को इन मामलों में आरोपी बनाया था।

जांच एजेंसी का आरोप

सीबीआइ ने सितंबर, 2013 में श्री शाह सहित 37 लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। जांच एजेंसी का आरोप था कि सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी का अपहरण कर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर कर दिया गया। सीबीआइ के अनुसार, चूंकि तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले का चश्मदीद गवाह था, इसलिए सबूत मिटाने के लिए अगले साल फर्जी एनकाउंटर में उसे भी मार डाला गया।

साजिश के लिए माफी मांगें सोनिया

फर्जी एनकाउंटर मामले से पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह को बरी किए जाने को सच्चाई की जीत करार देते हुए भाजपा ने दोहराया कि इससे कांग्रेस के षड्यंत्र और सीबीआइ के दुरुपयोग का पर्दाफाश हो गया है। मुंबई विशेष अदालत के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि कोर्ट ने भाजपा की बात साबित कर दी है।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति की कथित हत्या के मामले में तत्कालीन केंद्र सरकार के निर्देश पर फंसाया गया था। उन्होंने कहा शाह के खिलाफ कोई सुबूत नहीं थे और यह बात अब साबित हो गई है।

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इसे प्रतिशोधात्मक मामला करार देते हुए कहा कि उसमें वैधानिक तथ्यों की सर्वथा कमी थी। फैसला यही होना था। कोर्ट ने सिर्फ सच्चाई बयां की है। अदालत के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल था और खुद श्री शाह उसका हिस्सा थे।■

प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा

नहीं होगा रेलवे का निजीकरण : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 दिसंबर को दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीन स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान श्री मोदी ने रेलकर्मियों की बड़ी आशंका को दूर करते हुए कहा कि रेलवे के निजीकरण की बात कोरी अफवाह है। किसी भी हाल में रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। हम रेलवे के विकास के लिए अमीरों का पैसा लेंगे, गरीबों पर भार डालने का चलन अब बंद होगा। स्वच्छता अभियान के लिए नौ और रत्नों की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा, संस्कृति व धरोहरों के संरक्षण व उन्नयन का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि हमें खुद को विश्व के अनुरूप बनाना होगा, विश्व हमारी तरफ देख रहा है।

करीब 213 करोड़ की डीजल इंजन रेल कारखाना विस्तारीकरण योजना की आधारशिला रखने व 4500 अश्व शक्ति के डीजल रेल इंजन का लोकार्पण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इंजन में 96 प्रतिशत वस्तुएं स्वदेशी हैं, इसे सौ प्रतिशत तक लाना है। यह 'मेक इन इंडिया' की ओर बढ़ता हमारा कदम है, जिसे रेलवे से बहुत उम्मीदें हैं। देश के चारों कोनों में चार रेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करते हुए श्री मोदी ने रेलवे के संसाधनों का अन्य क्षेत्रों में भी लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था है, वहां दो तीन कमरे बनाकर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। अपनी सांसद निधि, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बेंच लगाने के लिए दे देने वाले श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि सभी सांसद, अपनी निधि से अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर

बेंच लगवाएं ताकि हजारों यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो सके।

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालयीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास करने के बाद पूरे विश्व में योग्य शिक्षकों की कमी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें यह जतन करना होगा कि 65 प्रतिशत युवाओं वाले इस मुल्क में इंटर के बाद ही शिक्षा की ऐसी संस्कृति पैदा करें कि भारत ही नहीं दुनिया से योग्य शिक्षकों की कमी समाप्त हो जाए। सवाल खड़े करने के बाद अपेक्षा करते हुए अपनी बात रखने के निराले अंदाज के क्रम में मोदी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्कूलों में हर शाम हम अपनी विरासतों व धरोहरों पर नाट्य मंचन करें। काशी में बाबा विश्वनाथ व मां गंगा के नाते देश विदेश से लोग आते हैं, अपने इन प्रयासों से हम उन्हें यहां रोक सकते हैं, रोजगार के अवसर पा सकते हैं। ऐसा ही पूरे देश में किया जा सकता है। योग पर भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दे दिया है। योग हमारी विरासत है और स्वस्थ समाज निर्माण में योग का बड़ा योगदान हो सकता है। इसके पूर्व वाराणसी हवाई अड्डा पहुंचे प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने स्वागत किया। श्री मोदी ने सबसे पहले लंका स्थित महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अस्सी घाट का निरीक्षण करते हुए स्वच्छता अभियान में लगी संस्थाओं व विभागों की सराहना भी की। ■

भाजपा अध्यक्ष का प्रवास

महाराष्ट्र

सवा करोड़ सदस्य बनाएगी भाजपा'

मुंबई में सवा करोड़ लोगों को भाजपा का सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश भाजपा काम कर रही है।

यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 जनवरी को मुंबई में पत्रकारों को दिया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम भाजपा नेता उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोरदार तरीके से शुरु किया गया है। अब तक पूरे देश में 2 करोड़ 85 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। मुंबई व महाराष्ट्र में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस समय मुंबई में 20 लाख सदस्य हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। श्री शाह ने 6 माह में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश में जन-धन योजना के तहत साढ़े 9 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ आम नागरिक उठा रहे हैं। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो घोषणाएं की थी, उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत विदेशों से काला धन वापस भारत लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पिछली सरकार स्विस बैंक खाता धारकों का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह सभी नाम एसआईटी को सौप दिया है और इसकी जांच की जा रही है।

श्री अमित शाह ने बताया कि भाजपा सरकार किसी भी तरह पूरे देश के हर घर को 2019 तक बिजली के कनेक्शन देना चाहती है। भाजपा शासित राज्य गुजरात व मध्यप्रदेश में भाजपा ने यह काम कर दिखाया है। केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में काम किया जा रहा है। बहुत जल्द केंद्र सरकार हर राज्य को नई तकनीक व आवश्यक बिजली प्रदान करने वाली है, जिससे पूरे देश में बिजली संकट समाप्त हो जाएगा और बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंच सकेगा। इसी प्रकार मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर दिशा में बेहतर काम कर रही है, जिससे आम जनता को सभी तरह की समस्याओं से निजात मिल रही है। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में उन्हें चुनाव में बहुमत हासिल होने वाला है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी वह सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदीजी के शासन काल में सर्वत्र उत्साह का माहौल है, जिसका लाभ भाजपा को मिल रहा है।

कर्नाटक

'कर्नाटक की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 जनवरी को बंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को

संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राज्य की जनता से 'कांग्रेस-मुक्त कर्नाटक' बनाने के लिए अधिकाधिक संख्या में भाजपा से जुड़ने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भाजपा के शासन में

कर्नाटक की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक थी, आज यह पांच प्रतिशत के आसपास आ गई है।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसानों का बहुत बुरा हाल है। कर्नाटक के 77 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में प्रतिदिन 20 हजार लोग भाजपा के सदस्य बन रहे हैं और मार्च 2015 तक यहां एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद देश और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सरकार 29 दिसंबर को बंगलुरु की चर्च स्ट्रीट पर कायराना विस्फोट करने वाले आतंकियों को सजा दिलाएगी। केंद्र सरकार इस धमाके के षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए कर्नाटक सरकार को हर संभव सहयोग कर रही है। इस घटना में जान गंवाने वाली श्रीमती भवानी के परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट, निष्क्रिय और शिथिल है। यह सरकार जनता के जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। जनता ने राज्य के विकास के लिए वोट दिया था लेकिन राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीतियां अपना रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राजग सरकार की पहले सात महीनों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2015 की शुरुआत देश को एक नई संस्था देकर की है। सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है जो योजना आयोग का स्थान लेगा। ''सहकारी संघवाद'' की संकल्पना पर आधारित नीति आयोग में प्रधानमंत्री के साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे और ये सब मिलकर 'टीम इंडिया' के रूप में काम करेंगे। ■

राव साहब पाटिल दानवे बने महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 जनवरी को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे को महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री दानवे श्री देवेंद्र फडणवीस की जगह लेंगे। विदित हो कि श्री फडणवीस हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। श्री दानवे मराठवाड़ा के जालना सीट से सांसद हैं। उन्होंने इस सीट पर लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। ■

विभिन्न दलों के सुशासन की तुलनात्मक क्षमता का लेखा-जोखा

24 दिसम्बर 2014 को सुशासन की पूर्व-संध्या पर आयोजित भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "Politics of Performance: A Comparative Study of Delivery of Good Governance by different political parties" -एक शोध पुस्तक का विमोचन किया गया।

विभिन्न राज्यों और विभिन्न राष्ट्रीय स्तरों पर देश की विभिन्न पार्टी की चार व्यवस्थाओं की शासन सम्बन्धी तुलना और उत्कृष्टता पर यह पुस्तक तैयार की गई है। इन व्यवस्थाओं में शासन मॉडलों के अन्तर्गत कांग्रेस, भाजपा, वाममोर्चा और विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों को लिया गया है।

इस पुस्तक में, विभिन्न शासन संकेतकों के आधार पर चार शासन मॉडलों के प्रदर्शनों की तुलना की गई है और सामाजिक-आर्थिक परिणाम निकाले गए हैं। इस पुस्तक प्रकाशन के पीछे विचार यह रहा है कि नागरिकों को प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के सुशासन प्रदान करने और उनकी क्षमताओं से परिचित कराया जाए। इस अध्ययन में, विभिन्न पार्टियों के शासनाधीन राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर शासन की उत्कृष्टता की तुलना और विश्लेषण करना है। इसके डाटा को 1991-2013 वर्षों के विभिन्न संसाधनों से तथा सभी राज्यों और दिल्ली (या अन्य उपलब्ध) एवं राष्ट्रीय स्तरों से इकट्ठा किया गया है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष के डाटा का विश्लेषण उस वर्ष के क्रमागत राज्य और केन्द्र में रही सत्तारूढ़ पार्टी के साथ किया गया है। इस प्रक्रिया से, भाजपा शासित, कांग्रेस शासित, क्षेत्रीय शासित पार्टी और राज्यों में वाममोर्चा शासित पार्टियों के साथ तुलना और विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक भाजपा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की स्थापना 2011 में की गई थी और यह पॉलिसी अध्ययन, विश्लेषणात्मक शोध और डाक्युमेंटेशन के लिए कार्य कर रही है।■

अमित शाह दोषमुक्त

✍ अरुण जेटली

मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति की कथित हत्या में शामिल होने संबंधी मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। मैं इस मामले की जांच शुरू होने, आरोपपत्र दायर होने, अमित शाह की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत दिये जाने के समय से ही इस पर लगातार नज़र रखे हुए हूं। मैंने राज्य सभा में विपक्ष का नेता होने की हैसियत से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 27 सितम्बर 2013 को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में मैंने भाजपा नेतृत्व के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग करने की बात कही थी। उस पत्र में मैंने इन दो मामलों के संबंध में इस प्रकार लिखा था :

''सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला''

वह मुठभेड़ जिसमें सोहराबुद्दीन शेख मारा गया वह एक ऐसी कार्रवाई थी जो केन्द्र सरकार के गुप्तचर ब्यूरो के निर्देश पर की गई थी। यह परिपाटी रही है कि जब गुप्तचर ब्यूरो को कोई जानकारी मिलती है और वह धीरे-धीरे उस पर आगे बढ़ती है, तो वह निशाने के प्रति सतर्कता बरतती है। तत्पश्चात निशाने को गिरफ्तार करने का जब एक अवसर सामने आता है तो उस कार्य में राज्य पुलिस को शामिल किया जाता है। सोहराबुद्दीन कुख्यात माफिया था जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय था और उसे पकड़वाने के लिए मध्य प्रदेश ने ईनाम घोषित कर रखा था। वह अवैध हथियारों का डीलर था। टाडा के अंतर्गत भी उसे दोष ठहराया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उज्जैन जिले में झरनिया गांव स्थित उसके परिसरों में ली गई तलाशी में 40 से ज्यादा एके-56 राइफलें, सैकड़ों एके-56 के कारतूस और सैकड़ों हथगोले मिले। विभिन्न राज्य सरकारों की पुलिस एजेंसियों ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था।

मैं उन कुछ लोगों में शामिल था जो पिछले तीन वर्ष से लगातार एक ही बात कह रहे थे कि अमित शाह पर ''बिना किसी सबूत'' के मुकदमा चलाया जा रहा है। सबूत का विस्तार से अध्ययन किए बिना, मीडिया ने सीबीआई की जानकारी के अनुसार रिपोर्ट किया। यहां तक कि मीडिया के लिए सीबीआई की फाइल में की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कोई खबर नहीं थी कि अमित शाह को फंसाना जरुरी है ताकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाया जा सके। मुझे संतोष इस बात का है कि भारत में स्वतंत्र न्याय प्रणाली है जिसने अमित शाह को दोषमुक्त ठहराया।

मुठभेड़ के बाद 24/25-11-2005 को उसके भाई ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। यह रिट याचिका भी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी। भारत के तत्कालीन अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, पहले से सोचे-समझे और पूर्व नियोजित तरीके से, पहले दिन अदालत में उपस्थित होकर केन्द्र सरकार से निर्देश लेने को तैयार हो गए। इसके बाद एटॉर्नी जनरल भारत सरकार के लिए उपस्थित हुए और गोपाल सुब्रमण्यम ने उनकी नियुक्ति करने वाली अदालत के आदेश के बिना खुद को एमिकस क्यूरी मनोनीत कर लिया। भारत सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो गई। हालांकि केन्द्र सरकार को सिर्फ एक औपचारिक पक्ष होना चाहिए था, तत्कालीन एटॉर्नी जनरल उपस्थित होते रहे और स्थगन प्रस्तावों का विरोध करते रहे। चूंकि सीबीआई के निश्पक्ष होने को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने अपनी देख-रेख में राज्य पुलिस में गुजरात पुलिस के अधिकारियों की एक टीम से जांच कराने का आदेश दे दिया। राज्य की पुलिस ने मुठभेड़ की फिर से रचना की, माननीय उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में वैज्ञानिक तरीके से जांच की और तीन आईपीएस अधिकारियों सहित अनेक पुलिस अधिकारियों को फंसाया और गिरफ्तार कर लिया। केन्द्र और एमिकस क्यूरी श्री गोपाल सुब्रमण्यम और अन्य की दलीलें सुनने पर, उच्चतम न्यायालय ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था, वह ये था कि जांच में अंतर्राज्यीय जटिलताएं हैं और मामले में आंध्र प्रदेश के दृश्टिकोण की जांच नहीं की गई है। वास्तव में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने गुजरात

पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया जो रिकॉर्ड में है।

सीबीआई ने मामले की जांच की लेकिन उन चार बिन्दुओं की जांच नहीं की जिनके आधार पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था जो बिन्दु गुजरात पुलिस की जांच में शामिल नहीं थे। इस मामले में आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण की गंभीरता से जांच नहीं की गई। इस मामले में लगता है कि सीबीआई का उद्देश्य गुजरात के राजनैतिक संस्थान को फंसाना, भारत की शासन व्यवस्था के संघीय चरित्र की बनावट को खारिज करना था। सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री श्री अमित शाह और साथ ही कानून मंत्री, परिवहन और संसदीय कार्य मंत्री को निशाना बनाया और उसका इरादा आखिर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाना था।

चौंकाने वाली बात तो ये है, जब सीबीआई के कानून विभाग ने बताया कि श्री अमित शाह के खिलाफ कोई मामला नहीं है, यही बात सीबीआई के पर्यवेक्षी अधिकारी ने इस ''टिप्पणी'' के साथ कही कि अमित शाह की गिरफ्तारी से सीबीआई के पास कुछ और गवाह खासतौर से पुलिस अधिकारी आ जाएंगे क्योंकि वे डरे हुए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह को गिरफ्तार करना आवश्यक है क्योंकि पूछताछ के अंतिम लक्ष्य नरेन्द्र मोदी तक पहुंचने के लिए ऐसा करना जरुरी है। इस टिप्पणी को सीबीआई के निदेशक श्री अश्विनी कुमार ने मंजूरी दे दी।

सीबीआई ने मुकदमा चलाने लायक सबूतों के बिना अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया। अमित शाह को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने गुजरात के दो भू-माफियाओं रमनभाई पटेल और दशरथभाई पटेल की झूठी गवाही पर भरोसा किया। आरोपपत्र में सीबीआई की थ्योरी के अनुसार, श्री अमित शाह ने मुठभेड़ के छह महीने बाद दोनों को कथित तौर पर बताया था कि सोहराबुद्दीन ने खुद के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। इस बात को न्याय संबंधी असाधारण स्वीकारोक्ति के रुप में शामिल कर लिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि रमनभाई पटेल और दशरथभाई पटेल दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और दोनों के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मामले चल रहे हैं। श्री अमित शाह के खिलाफ गवाही देने पर इन दोनों को गुजरात कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शंकरसिंह वाघेला की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में बधाई दी गई। इन दोनों गवाहों की गवाही उन्हें पासा (पीएएसए) हिरासत में मदद करने के लिए उनसे जबरन वसूली पर आधारित थी। गुजरात सरकार के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पासा के अंतर्गत इन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेने का कभी विचार ही नहीं किया गया। दोनों गवाहों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने किसी अजय पटेल के जरिये तीन किश्तों में श्री अमित शाह को 75-75 लाख रुपये दिये और इसके लिए उन्होंने अपने बयान में कुछ तारीखों का जिक्र किया है। उन्होंने कुछ तारीखें बताई हैं जब उन्होंने कथित रुप से कथित धनराशि श्री अजय पटेल को खुद जाकर सौंपी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वे उन सभी तारीखों पर मौजूद थे। यह गवाही अन्य बातों के अलावा इस आधार पर झूठी है कि कुछ तारीखों पर अजय पटेल भारत में नहीं थे और इस तथ्य की उनके पासपोर्ट से पुष्टि होती है। श्री अमित शाह के खिलाफ दायर आरोपपत्र में लगाए गए ओछे आरोपों की यह वास्तविकता है। श्री अमित शाह को गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आरोपपत्र पर जमानत दे दी और अन्य बातों के अलावा विस्तार से कहा कि श्री अमित शाह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती दी और सीबीआई के अनुरोध पर, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि श्री अमित शाह गुजरात से बाहर और सभी राजनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। वह दो वर्ष की अवधि तक गुजरात से बाहर रहे। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा।

''तुलसी प्रजापति मुठभेड़''

तुलसी प्रजापति का मामला सोहराबुद्दीन मामले का सीबीआई द्वारा किया गया विस्तार है। सीबीआई ने अदालत में इस मामले की जांच के लिए विशेष निवेदन किया। उनका तथाकथित मामला यह था कि तुलसी प्रजापति गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारियों की हिरासत से सोहराबुद्दीन के लापता होने के मामले में गवाह था तथा परिणामस्वरुप गुजरात पुलिस ने उसका सफाया कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में श्री अमित शाह के खिलाफ जिस एकमात्र सबूत का जिक्र किया है वह यह है कि वह भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी श्री आर. के. पांडियन से नियमित संपर्क में थे जो इस मामले में एक आरोपी हैं। विस्तृत समसामयिक रिकॉर्ड बताते हैं कि श्री आर. के. पांडियन की श्री अमित शाह के साथ इस घटना से काफी समय पहले से और घटना के बाद रोजाना टेलीफोन पर बातचीत होती थी क्योंकि वह राजनैतिक आंदोलनों और राजनैतिक गतिविधियों

पर नज़र रखने वाली राज्य पुलिस के पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर ब्यूरो का काम भी देख रहे थे। किसी भी राज्य के गृह मंत्री के लिए राजनैतिक आंदोलनों और राजनैतिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाली राज्य पुलिस के पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर ब्यूरो (खुफिया) के साथ संपर्क में रहना जरुरी है क्योंकि उसे नियमित आधार पर इन गतिविधियों के बारे में खुद जानकारी लेनी होती है। बिना किसी सबूत के तुलसी प्रजापति मामले में श्री अमित शाह के खिलाफ एक अलग आरोपपत्र दायर कर दिया गया। यह बात बेहद महत्वपूर्ण तरीके से गौर करने लायक है, हांलाकि सीबीआई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर काम कर रही थी और उसे तुलसी प्रजापति मामले में जांच का काम 11-04-2011 से 6 महीने के भीतर पूरा करने को कहा गया था, सीबीआई ने जान-बूझकर और राजनैतिक साजिश के तहत निर्देश का पालन नहीं किया और 04-09-2012 को आरोपपत्र दायर कर दिया ताकि गुजरात विधानसभा के चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले श्री अमित शाह को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा सके जो दिसम्बर 2012 से पहले होने थे। श्री अमित शाह को माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 08-04-2013 के आदेश में कहा कि इस मामले में अलग आरोपपत्र दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि सीबीआई ने खुद आरोप लगाया है कि दोनों मामले एक जैसे हैं और उसने आरोपपत्र को सोहराबुद्दीन मामले के आरोपपत्र के साथ मिला दिया जिसके परिणामस्वरुप सीबीआई एक बार फिर श्री अमित शाह को गिरफ्तार नहीं कर सकी।

''तुलसी प्रजापति और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया की गिरफ्तारी''

श्री गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री रह चुके हैं और इस समय पार्टी की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति नाम के किसी शख्स के बारे में उनके पास दूर-दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर कर दिया जिसमें उसने आरोप लगाया कि तुलसी प्रजापति का सफाया करने का गुलाब चंद कटारिया का मकसद राजस्थान के संगमरमर विक्रेता आर. के. मार्बल्स से धन ऐंठना था। सीबीआई के अनुसार इसके दो मकसद थे; पहला सोहराबुद्दीन मामने में गवाह का सफाया करने के लिए गुजरात पुलिस उसका सफाया करना चाहती थी और राजस्थान के गृह मंत्री संगमरमर विक्रेता से धन ऐंठने के लिए उसका सफाया करना चाहते थे। कैसा संयोग है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि श्री गुलाब चंद कटारिया ने गुजरात पुलिस के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री डी. जी. वंजारा से कथित तौर पर 26/12/2005 और 28/12/2005 के बीच उदयपुर के सर्किट हाउस में कथित मुलाकात की थी। उनकी उपस्थिति के बारे में सीबीआई के पास जो सबूत है वह यह है कि श्री गुलाब चंद कटारिया का निजी सचिव उस अवधि के दौरान उसी सर्किट हाउस में रुका हुआ था और श्री डी. जी. वंजारा भी उसी सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। लेकिन राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि श्री गुलाब चंद कटारिया अपनी पत्नी के साथ 25/12/2005 को मुंबई चले गए थे और वह 2/1/2006 तक वहां रहे। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए तथा अपनी पत्नी के साथ नया वर्ष मनाने के बाद वे 2/1/2006 को जयपुर लौट आए।''

ऊपर दी गई बातों से यह स्पष्ट है कि अमित शाह के खिलाफ तत्कालीन राजनैतिक सरकार के इशारे पर दायर किए गए। कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कोई सबूत स्वीकार करने योग्य नहीं है। बरी करने संबंधी अमित शाह की अर्जी का सीबीआई और सोहराबुद्दीन के भाई दोनों ने विरोध किया था। अदालत ने दोनों के वकीलों को सुना। आरोप निराधार थे। यह सच्चाई चिंता का विषय है कि सीबीआई ने उस समय अपना दुरुपयोग होने दिया।

चूंकि मैंने जांच के दौरान और आरोपपत्र दायर होने के बाद कथित सबूत का विश्लेषण किया था, मैं उन कुछ लोगों में शामिल था जो पिछले तीन वर्ष से लगातार एक ही बात कह रहे थे कि अमित शाह पर ''बिना किसी सबूत'' के मुकदमा चलाया जा रहा है। सबूत का विस्तार से अध्ययन किए बिना, मीडिया ने सीबीआई की जानकारी के अनुसार रिपोर्ट किया। यहां तक कि मीडिया के लिए सीबीआई की फाइल में की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कोई खबर नहीं थी कि अमित शाह को फंसाना जरुरी है ताकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाया जा सके। मुझे संतोष इस बात का है कि भारत में स्वतंत्र न्याय प्रणाली है जिसने अमित शाह को दोषमुक्त ठहराया। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

विज्ञान के लाभ को सबसे गरीब तक पहुंचाएं : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के लाभों को सबसे गरीब, सबसे दूरस्थ और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के एक समृद्ध भविष्य के लिए हमें विज्ञान, तकनीकी और नवाचार को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सबसे शीर्ष पर रखने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने 3 जनवरी को मुंबई में 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने भाषण में कहा कि अधिक व्यावहारिक कृषि, ग्रामीण भारत के लिए उपयुक्त एवं वहनीय तकनीकें, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, स्वच्छ तकनीकों को वहन बनाने योग्य और भारत को एक अग्रणी विनिर्माण राष्ट्र, ज्ञान के केंद्र और तकनीकोन्मुखी उद्योग जगत जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे वैज्ञानिकों के समक्ष थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति एवं मानव विकास, विज्ञान तथा तकनीकी से जुड़ा हुआ है और आज चीन ने विश्व में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो दर्जा हासिल किया है वह उसके विज्ञान और तकनीकी गतिविधियों से ही संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं मानव विकास पर किया जाने वाला कोई भी विचार विमर्श राजनीतिक निर्णयों, सामाजिक विकल्पों, समानता, नैतिक मूल्यों एवं पहुंच जैसे सवालों से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव विकास हमारे देश के वैज्ञानिक लक्ष्यों का एक बड़ा उद्देश्य और प्रेरणादायी

बल रहा है और विज्ञान ने आधुनिक भारत को बदलने में काफी मदद की है।

प्रधानमंत्री ने कहा जब भी विश्व ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद किए तो हमारे वैज्ञानिकों ने अनूठी पहल की और हमें नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि जब भी हमसे विश्व ने सहयोग मांगा, तो हमारे वैज्ञानिकों ने खुलेपन का परिचय दिया और यही हमारे समाज में अंतर्निहित है। उन्होंने मंगलयान को मंगल की कक्षा में पहले ही प्रयास में स्थापित करने और चक्रवात हुदहुद की सटीक भविष्यवाणी करने में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की जिसके वजह से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह देश में व्यापार करने में आसानी की बात करते हैं तो वह यह भी चाहते हैं कि देश में शोध एवं विकास करने में भी आसानी हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने अथवा जारी करने में अधिक समय नहीं लिया जाये और वैज्ञानिक विभागों को शोध संबंधी गतिविधियों के लिए ऐसे निर्णयों को लेने में पूरा लचीलापन रखना होगा। उन्होंने जैव तकनीकी, नैनो साइंस, कृषि एवं क्लीनिकल शोध के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए स्पष्ट नियामक नीतियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सरकारी विभाग में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो अपने क्षेत्र से संबद्ध कार्य में विज्ञान एवं तकनीक पर अधिक ध्यान दे और ऐसी गतिविधियों के लिए विभाग के बजट में से कुछ प्रतिशत धनराशि का आवंटन करे। उन्होंने कहा 'हमें अपनी विश्वविद्यालय प्रणाली को देश में शोध एवं विकास संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में अग्रणी रखना है' विश्वविद्यालयों को अत्यधिक नियम कानूनों तथा अड़चन भरी प्रक्रियाओं से मुक्त भी करना है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत से पहल करते हुए विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने विश्व में अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि उसने शोध के क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के अपने गौरव को बरकरार रखना है, समाज में विज्ञान के प्रति लोगों की उत्सुकता को पुनर्जीवित करना है, हमारे बच्चों में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति प्रेम को फिर से जगाना है और देश के वैज्ञानिकों को कल्पना करने, सपने देखने और उन पर काम करने के लिए प्रेरित करना है। ■

दिल्ली विधानसभा चुनाव पर विशेष

दिल्ली में भाजपा को मिल सकता है पूर्ण बहुमत

✍ संजीव कुमार सिन्हा

दिल्ली में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार और तैयारी को लेकर जोर-शोर से जुटी हैं। चुनावी मुद्दों की फेहरिस्त लंबी है, जिनमें बिजली की बढ़ती दरें, पानी और आवास की कमी, महिलाओं की सुरक्षा, पार्किंग और जाम की समस्या, इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना प्रमुख हैं। भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी।

दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीट है जबकि लोकसभा की 7 सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सातों सीट पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा के हिसाब से भाजपा 60 सीटों पर नंबर वन थी जबकि आप 10 सीटों पर सबसे आगे थी।

2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 68 सीटों पर लड़ी थी, 31 सीटों पर उसने जीत दर्ज की, जबकि कुल 33 फीसदी वोट उसके हिस्से में आये थे। भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर लड़ी थी, एक पर उसे जीत मिली और एक फीसदी वोट उसके हिस्से में आया था। आप ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जिसमें से उसे 28 सीटों पर जीत मिली थी। उसे कुल 29 फीसदी वोट मिले थे।

कांग्रेस ने भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन उसके हिस्से में आयी थी महज 8 सीटें। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 25 फीसदी।

पहले लोकसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा और उसके पश्चात् झारखंड और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की ऐतिहासिक विजयों को देखते हुए दिल्ली में जनता भाजपा की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है। पार्टी में विभिन्न दलों, समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला शुरू है। पिछली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब आकर रह गई थी। जिस प्रकार से भाजपा सरकार विकास की गारंटी बन रह रही है और देश भर में उसके पक्ष में लहर चल रही है, उसे देखते हुए इस बार दिल्ली के मतदाता भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप सकते हैं।

बसपा 69 सीटों पर लड़ी थी लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पायी। बसपा को मात्र पांच फीसदी वोट मिले थे।

जनता दल (यू) ने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिसमें से एक सीट पर उसने जीत दर्ज की थी। उसे महज एक फीसदी वोट मिला था। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रामबीर शौकीन ने जीत दर्ज की थी।

दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है तो राष्ट्रीय राजधानी भी। लेकिन यह बात कचोटती है कि दिल्ली का जैसा विकास होना चाहिए था, वैसा विकास नहीं हो पाया। इसका कारण है कि यहां कांग्रेस लगातार 15 साल सत्ता में रही। उसने जन-समस्याओं की सुध नहीं ली। आज दिल्ली प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और दिल्ली का निवासी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। बिजली आपूर्ति में अनियमितता, पीने के पानी का अभाव, स्कूली और कॉलेज शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक कमी, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन की दुर्दशा, गरीबों के लिए शालीन और पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी। ये सभी उपरोक्त समस्याएं दिल्ली में व्याप्त गम्भीर संकट को बयान करती हैं। शीला दीक्षित की दिल्ली और केन्द्र की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त थी। राष्ट्रमंडल खेलों के सत्तर हजार करोड़ रूपये, 2जी स्पेक्ट्रम के एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपये जैसे अनेक घोटालों से देश व प्रदेश का विकास अवरूद्ध हो गया था।

2013 में दिल्ली में एक नयी पार्टी - आम आदमी पार्टी आई। इसके नेता ने समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया और अपने संकीर्ण हितों को साधने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन का इस्तेमाल कर लिया। यह पार्टी छल, छद्म और झूठ की राजनीति करती है।

गत विधानसभा चुनाव में जनादेश 'आप' को विपक्ष में बैठने और भाजपा को सरकार बनाने का मिला। चूंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था

इसलिए पार्टी ने जोड़-तोड़ कर सिद्धांतहीन सरकार बनाने से इनकार कर दिया लेकिन 'आप', जो बात-बात में सैद्धांतिक राजनीति का राग अलापती थी, उसने कांग्रेस पार्टी से अनैतिक गठजोड़ कर सरकार बना लिया।

आम आदमी पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसने अपने शासन के 49 दिनों में बड़ी-बड़ी बातें करने और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार के मामले में कहा था कि पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर कुछ नहीं किया। सत्ता में आते ही सुर बदल गए। बच्चों की कसम खाई थी कि गठबंधन नहीं करूंगा लेकिन किया। इसके मंत्री ने विदेशी महिला से दुर्व्यवहार किया। कहा था कि पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन यह नहीं हुआ।

वादा किया था कि बिजली के रेट आधे करेंगे लेकिन नहीं किए गए। कहा था, सरकारी स्कूलों को सुधारेंगे लेकिन सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और अंत में अपने नाकारेपन का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए।

आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी है। झूठे आरोप लगाना और सस्ती राजनीति करना यह उनके चरित्र में है। गत चुनाव में नए टोटके कर इसने दिल्ली की जनता को भरमाया। लेकिन अब तो किसी भी मुद्दे पर 'रायशुमारी' नहीं हो रही है। अब तो यहां एक व्यक्ति की तानाशाही चलती है। पार्टी के बड़े नेता शांति भूषण ने पार्टी नेतृत्व पर हमला करते हुए ठीक ही कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है।

आम आदमी पार्टी के नेता श्री प्रशांत भूषण ने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात खुलकर कही एवं आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों से सेना हटाने की बात, अफ़जल गुरू और अजमल कसाब की फांसी का विरोध कर रहे मुजफ्फर बट्ट और बाबू मैथ्यू को श्रीनगर और बैंगलोर लोक सभा से टिकट देना, अरविन्द केजरीवाल द्वारा बटला हाऊस और इशरत जहा एनकाऊंटर को फर्जी बताना जो कि न्यायालय में पहले ही साबित हो चुका है कि बटला हाऊस में मारे गए-इण्डियन मुजाहिदीन के आतंकी थे। इशरत जहां लश्करे तैयबा के लिए काम करती थी। ओखला में देश द्रोही व समाज की शान्ति को भंग करने वाले व्यक्ति अमानतुल्ला खान को विधायक का टिकट देकर देश-द्रोही मानसिकता को साबित किया, जो अतिनिंदनीय हैं।

चुनाव का समय है। इस समय अनेक राजनीतिक दल बरसाती मेढ़क की तरह टर्र-टर्र करने लगते हैं, लेकिन भाजपा ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विभिन्न मुद्दों को लेकर निरंतर सक्रिय रहती है। चाहे सुरक्षित दिल्ली का मसला हो, चाहे अनियमित कॉलोनियों के विकास का मुद्दा हो, चाहे पूर्वांचल और पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याएं हों, भाजपा ने सदैव संघर्ष किया।

भाजपानीत केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता हित में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा रेणुका डैम बनाने को प्राथमिकता देते हुए पहले ही बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किया जाना, रेणुका डैम के साथ-साथ मुनक नहर द्वारा दिल्ली को शीघ्रातिशीघ्र स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की भाजपा की प्रतिबद्धता का सूचक हैं।

श्री तेजेन्द्र खन्ना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की लगभग 50 फीसदी आबादी झुग्गी-झोपड़ी और अनाधिकृत कालोनियों में रहती है। लगभग पिछले एक दशक से दिल्ली सरकार वायदा करती रही, कि इन गरीब परिवारों के लिए सस्ती और टिकाऊ आवासीय सुविधा उपलब्ध करायेगी। राजीव रत्न आवास योजना के तहत 4 लाख मकान बनाने हेतु किए गये वायदे का नाटक दिल्लीवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा साबित हुआ। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा नीत राजग सरकार ने दिल्ली की लगभग 895 अनधिकृत कालोनियों को पास कर दिल्ली की जनता को राहत दी, उन कालोनियों में पहले 6 माह में विकास के कार्यों को प्रारम्भ कर रजिस्ट्री भी खोली जायेगी।

पिछले सात महीनों में देश का कायापलट हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाले भाजपा नीत केंद्र सरकार की जन-नीतियों से देश में सकारात्मक माहौल बना है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा और उसके पश्चात् झारखंड और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की ऐतिहासिक विजयों को देखते हुए दिल्ली में जनता भाजपा की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है। पार्टी में विभिन्न दलों, समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला शुरू है। पिछली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब आकर रह गई थी।

जिस प्रकार से भाजपा सरकार विकास की गारंटी बन रह रही है और देश भर में उसके पक्ष में लहर चल रही है, उसे देखते हुए इस बार दिल्ली के मतदाता भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप सकते हैं। ■

भाजपा बिहार प्रदेश कार्यसमिति बैठक

देश भर में भाजपा की बढ़ रही ताकत से बेचैन विरोधी दल बना रहे महागठबंधन : रामलाल

भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार व लालू-नीतीश मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। विद्यापति भवन में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन 5 जनवरी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राम लाल ने कहा कि 2014 भाजपा का वर्ष रहा था, 2015 भी भाजपा का ही वर्ष होगा।

आजादी के बाद पार्टी को पहला मौका मिला देश में सर्वाधिक विधायक और सांसद बनाने का। अब तक देश भर में भाजपा के एक हजार से अधिक विधायक हो गये हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसदों-विधायकों की संख्या न्यूनतम पर पहुंच गयी है।

आनेवाले वर्षों में उसके सांसदों-विधायकों की संख्या और नीचे आयेगी। हरियाणा में भाजपा चार से 47 पर पहुंच गयी, महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाया, झारखंड में भाजपा गंठबंधन की सरकार बनी और जम्मू-कश्मीर में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। श्री रामलाल ने कहा कि भाजपा की बढ़ती ताकत से विरोधी बेचैन हैं। वे मान चुके हैं कि वे अकेले भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए महागंठबंधन बना रहे हैं।

दिल्ली में जनता परिवार की बैठक हुई, जिसमें उसके नेता तक बड़ी संख्या में नहीं जुट पाये। भाजपा विरोधी दल कितना भी भ्रम पाल लें, जनता अब उनके पक्ष में नहीं आनेवाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने सात माह के शासनकाल में जो काम किये, उससे देश-दुनिया में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ लगाने का काम किया।

इससे पहले भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने बिहार को भ्रष्टाचार-अपराध और लालू-नीतीश से बिहार को मुक्त कराने का संकल्प लिया है। यह प्रस्ताव विधायक व पार्टी प्रवक्ता डॉ. उषा विद्यार्थी ने प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य प्रवक्ता श्री विनोद नारायण झा, प्रदेश महामंत्री डॉ. संजीव चौरसिया, सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहनवाज हुसैन ने समर्थन किया। तीन घंटे तक बहस के बाद राजनीतिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

भाजपा कार्यसमिति की बैठक

संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार को फिर से पटरी पर लाने, विश्वासघाती नेताओं से निबटने, विधानसभा चुनाव में मिशन 175. का लक्ष्य हासिल करने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने, बिहार में 50 लाख सदस्य बनाने, सत्ताधारी दल के झूठ का खुलासा करने की योजना पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुटेंगे और घर-घर जाकर लोगों को भाजपा से जोड़ेंगे। संगठन को हम और धारदार बनायेंगे और बिहार की जदयू सरकार की कमियों को उजागर करेंगे।

बिहार में अपने दम पर स्पष्ट व

पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 6 जनवरी को संपन्न हो गयी।

बैठक में भाजपा नेताओं ने संकल्प लिया कि वे बिहार की जनविरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी जदयू-राजद-कांग्रेस महागंठबंधन की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पार्टी ने 'जिसकी केंद्र में सरकार, उसकी प्रदेश में सरकार, चलो चलें मोदी के साथ, तभी होगा बिहार का विकास' का नारा दिया है।

कार्यसमिति की बैठक के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद व पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2010 में बिहार की जनता ने सत्ता पर काबिज होने का जनादेश भाजपा व जदयू को दिया था। नीतीश कुमार ने भाजपा से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी, तब उन्हें बिहार की सत्ता भी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया।

उन पार्टियों के दम पर सत्ता में बने हुए हैं, जिन्हें बिहार की जनता ने न केवल पिछले चुनाव में नकार दिया था, बल्कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनका सूपड़ा साफ कर दिया।उन्होंने बिहार की जनता का आह्वान किया कि बिहार में सत्ता उन हाथों में सौंपें, जो राज्य में पारदर्शी व उत्तरदायी सरकार दे सके। श्री यादव ने कहा कि बिहार वह जीवंत राज्य है, जो देश की राजनीति के नये मानक तय करता है। इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार ही नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा व दशा तय करनेवाला होगा।

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने अवसरवादियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है।

उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि आतंकराज और जंगलराज में क्या अंतर है? मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को 18 साल तक भाजपा कनफूंकवा नहीं लगी और आज अचानक कनफूंकवा कैसे बन गयी? उन्होंने दावा किया कि पिछले आठ वर्षो में बिहार में विकास के जो भी काम हुए, वे भाजपा के कारण हुए। भाजपा के अलग होते ही राज्य में सड़क निर्माण की गति में 23 फीसदी की कमी आ गयी है। विकास के सभी काम अधूरे पड़े हैं। ■

राजनीतिक प्रस्ताव में क्या-क्या

- वाजपयी, नरेन्द्र मोदी व अमित शाह के मार्गदर्शन में बिहार को उच्च स्थान दिलायेंगे
- प्रशासन में भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेवारी खत्म करेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 11 करोड़ बिहारियों का विकास करेंगे।
- बिहार को जंगलराज और भ्रष्टाचार से बचोंगे।
- विकसित, समृद्ध, आत्मविश्वासी और गौरवशाली बिहार बनायेंगे।
- केन्द्र सरकार के साथ मिलकर बिहार का चहुंमुखी विकास करेंगे।
- बिहार में पारदर्शी सरकार बनायेंगे।
- गरीबों, अतिपिछड़ों और महादलितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
- हर गरीब को रहने के लिए मुफ्त घर व पेयजल देंगे।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार के लिए काम होगा।
- सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध होगा।

पृष्ठ 8 का शेष...

उड़ीसा में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी : अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भरोसा जताया कि ओड़िशा में भाजपा की अपनी सरकार बन सकेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक ओड़िशा में भाजपा का प्रदर्शन का सम्बन्ध है पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाने में बहुत सफल रही है। पार्टी की संगठनात्मक शक्ति को भी मजबूत किया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगा और वह अपनी सरकार बनाएगी। ओड़िशा में अपनी दो दिन की यात्रा समाप्त करने पर उन्होंने कहा कि हमें बीजू-जनता दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस लड़ाई को तार्किक परिणति तक ले जाएंगे। पिछले 14 वर्षों में अन्य राज्यों के मुकाबले ओड़िशा का उतना विकास नहीं हुआ है। विकास गति नीचे गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारी बहुमत लेकर शासन कर रहे थे, फिर भी वे आशा के अनुरूप विकास गति प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि चिट फंड घोटाले में 10 लाख लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई गंवाई, जबकि सत्ता में बैठे लोगों ने इस घोटाले में इस गाढ़ी कमाई को अपनी जेबों में रख लिया।■

दिल्ली भाजपा की कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न

मोदी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य किया है : अमित शाह

गत 30 दिसंबर को भाजपा दिल्ली प्रदेश की नवगठित कार्यसमिति की पहली बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदेमातरम के गायन से हुई। इस बीच पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सुनील वैद्य और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के निधन पर शोक प्रस्ताव और दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, संगठन महामंत्री श्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी श्री प्रभात झा, अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय, केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, सांसद श्री विजय गोयल, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री प्रवेश साहिब सिंह ने सम्बोधित किया और सांसद एवं महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी ने राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री आशीष सूद एवं श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा किये जाने के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 भाजपा के इतिहास में अविस्मरणीय विजय वर्ष रहा है। यह सफलता हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग का परिणाम है। जनसंघ की स्थापना से लेकर भाजपा तक सभी कार्यकर्ताओं का सपना आज पूरा हुआ। इससे पहले भाजपा ने देश को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में प्रधानमंत्री दिया था। मोदी सरकार के विषय में विरोधी कुछ भी कहें जनता ने चार राज्यों में भाजपा को जीत दिलाकर यह दिखा दिया है कि मोदी सरकार का कार्य संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए भी बड़े-बड़े फैसले लिये गये हैं जिनमें अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का भी फैसला है। दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेंगे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि मैं चुनाव प्रबंधन विज्ञान का छात्र हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि विरोधियों के झूठ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का मतदाता आपके साथ है। उन्होंने दिल्ली के कार्यकर्ताओं के नाम संदेश में कहा कि अगर दिल्ली भाजपा का कार्यकर्ता आलस्य त्याग कर चुनाव समर में उतरेगा तो जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार की शंका और शिकायत के निवारण के लिए संगठन महामंत्री श्री रामलाल के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। अन्य राज्य भी जहां अगले वर्ष चुनाव होंगे दिल्ली भाजपा से बहुत उम्मीद रखते हैं। मोदी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य किया है। देश का आर्थिक विकास हो रहा है और विदेश में भी भारत का सम्मान बढ़ा है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रत्येक घर जाने और संपर्क करने को कहा (नोक एवरी डोर कान्टेक्ट एवरी वर्कर)। विरोधियों की आलोचनाओं पर विशेष ध्यान न दें और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें। उन्होंने नारा दिया जिसकी केन्द्र में सरकार उसी की राज्य में सरकार।

सांसद श्री प्रभात झा ने बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि आज देश में सबसे अधिक दलित सांसद, पिछड़ा वर्ग के सासंद, विधायक भाजपा के हैं। दिल्ली के कार्यकर्ताओं से आवाहन करता हूँ कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 50 से 60 सीटों पर जीत दिलाकर विधायकों की संख्या बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करें।

अपने स्वागत भाषण में श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने दिल्ली की अच्छी सेवा की है और उनकी उपलब्धियां प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी नगर निगमों के कार्य में सुधार का स्कोप है। उन्होंने केन्द्र में मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुये कहा कि सरकार माइक्रो डिटेलिंग रिजल्ट के साथ कार्य कर रही है। कल अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के संबंध में की गई घोषणा इसका उदाहरण है। ■

भाजपा का युगांतकारी विस्तार तथा कांग्रेस की ऐतिहासिक पराभव

देश भर में भाजपा के 1058 विधायक और कांग्रेस के 949

✍ राम नयन सिंह

भारतीय राजनीति में अलग पहचान वाली राष्ट्रवादी पाटी भाजपा का दिनोंदिन राष्ट्रव्यापी विस्तार हो रहा है। यह अभूतपूर्व विस्तार न केवल भाजपा के लाखों समर्पित कार्यकर्त्ताओं के कारण है, बल्कि डॉ. मुखर्जी, दीनदयाल, अटलजी, आडवाणीजी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे अनगिनत नेताओं के संगठन-प्रबंध कौशल का भी परिणाम है।

देश के राजनैतिक परिदृश्य में ऐसा पहली बार हुआ है, जब देश भर में भाजपा के कुल विधायकों की संख्या कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या से ज्यादा हुई है। यही नहीं आजादी बाद यह पहली बार हुआ है जब भाजपा के सभी विधायकों की संख्या 1000 को पार की है। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है और लगता है कि यह स्थायी परिवर्तन है। वर्ष 2014 देश के इतिहास का वह साल है जब कांग्रेस अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंची तथा राजनैतिक परिदृश्य पर भाजपा का व्यापक विस्तार हुआ। 'द् हिन्दू' में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अशोका यूनिवर्सिटी के पोलिटिकल डॉटा सेंटर द्वारा 1961 से संग्रहित आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 वह पहला वर्ष है जब देश भर में भाजपा के सभी विधायकों की संख्या 1058 जा पहुंची, वहीं कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या सिमट कर 949 हो गई। भाजपा के राजनैतिक इतिहास में यह सबसे बड़ी संख्या है, जबकि सिर्फ वर्ष 1977 और वर्ष 1979 में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 1000 से कम हुई है। यही नहीं, 2014 में कांग्रेस के सभी विधायकों की संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर है।

देश के राजनैतिक इतिहास में वर्ष 2014 कई मायनों में ऐतिहासिक है। 25 वर्ष बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। गठबंधनों का अनावश्यक दबाव कम हुआ। लोक सभा में भाजपा पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सकी। भाजपा के सांसदों की संख्या 282 तक जा पहुंची। उल्लेखनीय है कि लोक सभा में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है वह आजादी के बाद अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची। लोक सभा में उसके कुल सांसदों की संख्या मात्र 44 पर सिमट गई और ऐसी हालत में पहुंच गई कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी प्राप्त न हो सका। लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए न्यूनतम 54 सांसदों की आवश्यकता होती है।

भाजपा के इस ऐतिहासिक विस्तार के कई मायने हैं। भौगोलिक रूप में भाजपा का देशव्यापी विस्तार हुआ है। देश के हर कोने से राज्यों की विधान सभाओं में भाजपा के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुने गए। उत्तर-भारत में भाजपा का दबदबा रहा और पश्चिम-भारत में कांग्रेस से दुगुनी संख्या में भाजपा के विधायक चुन कर आए। पूर्वी-भारत में कांग्रेस से कड़ा मुकाबला रहा। हालांकि उत्तर-पूर्व में कांग्रेस अब भी कायम है, लेकिन दक्षिण-भारत में कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ है। यही नहीं आने वाले वर्षों में कांग्रेस का बचा-खुचा प्रभाव निरंतर कम होगा। 2016 में असम और 2018 में कर्नाटक में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होने की संभावना है।

भाजपा के इस ऐतिहासिक विस्तार के कई मायने हैं। भौगोलिक रूप में भाजपा का देशव्यापी विस्तार हुआ है। देश के हर कोने से राज्यों की विधान सभाओं में भाजपा के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुने गए। उत्तर-भारत में भाजपा का दबदबा रहा और पश्चिम-भारत में कांग्रेस से दुगुनी संख्या में भाजपा के विधायक चुन कर आए। पूर्वी-भारत में कांग्रेस से कड़ा मुकाबला रहा। हालांकि उत्तर-पूर्व में कांग्रेस अब भी कायम है, लेकिन दक्षिण-भारत में कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ है। यही नहीं आने वाले वर्षों में कांग्रेस का बचा-खुचा प्रभाव निरंतर कम होगा।

2016 में असम और 2018 में कर्नाटक में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होने की संभावना है।

भाजपा का विस्तार

वैसे तो भाजपा का गठन 1980 में हुआ, लेकिन इसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जन संघ की स्थापना 1951 में हुई थी और उसी साल प्रथम आम चुनाव में ही उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। उन दिनों देश भर में कांग्रेस की तूती बोलती थी तथा संसद व राज्यों की विधायिकाओं में जन संघ के नाम-मात्र के जन प्रतिनिधि होते थे। वर्ष 1967 तक आते-आते राजनीतिक ताकत के रूप में जन संघ ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस वर्ष पहली बार कांग्रेस का वर्चस्व टूटता दिखा और कई राज्यों में उसकी हार हुई। जन संघ और वामपंथियों ने मिल कर कई राज्यों में सरकार बनाई।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपात काल की घोषणा कर दी जिसका व्यापक विरोध हुआ। नतीजा 1977 के चुनावों में देखने को मिला। कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी जिसमें जन संघ भी शामिल था। भारतीय राजनीति का यह पहला प्रयोग विफल हो गया और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। राज नारायण और मधु लिमये जैसे समाजवादियों ने जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की सदस्यता रखने का विरोध किया। इससे जनता पार्टी में बिखराव हुआ। वर्ष 1980 में जन संघ घटक ने अपने को पुनर्गठित किया। जनता पार्टी में शामिल इसके नेता एक मंच पर आए। नई पार्टी का जन्म हुआ और इसका नाम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रखा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देशव्यापी उमड़ी सहानुभूति के दौरान 1984 में हुए चुनावों में भाजपा को दो सीटें मिलीं।

लेकिन वर्ष 1989 में जनता दल के साथ सीटों के तालमेल से इसे 89 सीटें मिलीं। हालांकि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर मतभेदों के बाद भाजपा ने सरकार से हटने का फैसला किया। 1991 के चुनावों में पार्टी ने 120 सीटों पर सफलता हासिल की। हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद चार राज्यों में भाजपा की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।

केंद्र में भाजपा की पहली सरकार वर्ष 1996 में बनी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय सदन में पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाया और महज 13 दिनों में सरकार गिर गई। 1996 के चुनावों में पार्टी को 161 सीटें मिली थीं।

इसके बाद 1998 में पार्टी ने 182 सीटें हासिल की। इसी समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का स्वरूप सामने आया। सरकार में समता पार्टी, अन्नाद्रमुक, शिव सेना, अकाली दल और बीजू जनता दल शामिल हुई। तेलुगूदेशम पार्टी ने इसे बाहर से समर्थन दिया। लेकिन ये सरकार भी 13 महीने ही चल सकी और अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई।

लेकिन ठीक उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की अगुआई में एनडीए फिर सत्ता में आई और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सरकार पूरे पाँच साल चली लेकिन वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी फिर कांग्रेस के हाथों में गई।

जनसंघ-भाजपा और कांग्रेस

वर्ष	भाजपा (विधायक)	कांग्रेस (विधायक)
1969	211	1625
1975	189	2188
1984	224	2013
1999	707	1280
2004	909	1129
2014	1058	949

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि देशव्यापी स्तर पर वर्ष 1969 से भारतीय जन संघ एक राजनैतिक संगठन के रूप में अपनी उपस्थिति का अहसास कराया, लेकिन यह उपस्थिति कांग्रेस की तुलना में काफी कम थी। कमोबेश यह स्थिति वर्ष 1989 तक बनी रही। वर्ष 1999 तक आते-आते पूरे देश में भाजपा के कुल विधायकों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई और यह संख्या 707 पहुंच गई।

वर्ष 1999 के बाद भाजपा का विस्तार निरंतर बढ़ता गया। जैसे-जैसे भाजपा का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे-वैसे कांग्रेस सिकुड़ती गई और 2014 तक आते-आते कांग्रेस अब तक के न्यूनतम स्तर 949 विधायकों तक सिमट गई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का यह ऐतिहासिक संकुचन निरंतर जारी है।

महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, बिहार जैसे कई बड़े राज्यों में तो कांग्रेस तीसरे-चौथे स्थान तक जा पहुंची है। जिस तरह से देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस-विरोधी माहौल बढ़ रहा है उससे तो यही लगता है कि अगले आम चुनावों तक आते आते शायद ही किसी बड़े राज्य में कांग्रेस की सरकार बची रह जाए। ■

(स्रोत: द् हिंदू व बीबीसी हिंदी)

अटलजी का प्रथम अध्यक्षीय भाषण : भाग - 3

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

- अटल बिहारी वाजपेयी

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष बने थे। बम्बई (अब मुम्बई) में आयोजित राष्ट्रीय परिषद (28-30 दिसम्बर 1980) में अटल जी के अध्यक्षीय भाषण ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति को जागृत किया। यह सचमुच में एक ऐतिहासिक भाषण था। गतांकों से हम उनके भाषण को कमल संदेश के सुधी पाठकों के लिए शृंखलाबद्ध प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है तीसरा भाग:-

विफलता के बारह महीने

बारह महीने बीत गए। दिल्ली में अभी तक काम करने वाली सरकार के दर्शन नहीं हुए हैं।

संसद है। उसका शीतकालीन अधिवेशन अभी-अभी समाप्त हुआ है। 24 दिनों में 10 अध्यादेशों पर मुहर लगाकर उसने नया रिकार्ड कायम किया है। निरोधक नजरबंदी जैसे काले कानून को पारित करने में उसने आधी रात तक परिश्रम करने की कर्त्तव्यपरायणता दिखाई है।

14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा था 'जब घड़ी आधी रात का घण्टा बजाएगी और जब विश्व सो रहा होगा तब भारत एक नए जीवन तथा स्वतंत्रता में जागेगा।'

दासता की नई बेड़ियां

22 दिसंबर 1980 को राज्यसभा द्वारा आधी रात को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की पुष्टि देखकर कोई यह भी कह सकता था कि-'जब सारा भारत सो रहा है, तब जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों को रोटी देने के बजाए उसकी आजादी को छीनने के लिए नई बेड़ियां गढ़ने में लगे हैं।'

सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी जगह है। मिनर्वा मिल्स के मामले में उसने पुन: अपने इस दृष्टिकोण को दोहराया है कि हमारे संविधान के कुछ आधारभूत तत्त्व हैं जिनके साथ संसद खिलवाड़ नहीं कर सकती। किंतु सरकार उस निर्णय को रद्द कराने पर तुली हुई है। सर्वोच्च न्यायलय को प्रगति के रास्ते में रुकावट के रूप में चित्रित किया जा रहा है। जजों के अनेक स्थान खाली पड़े हैं।

प्रेस सामान्यत: अपने दायित्व के प्रति जागरूक है। भागलपुर में पुलिस द्वारा हवालातियों की आंखें फोड़ने का पैशाचिक कृत्य न जाने कब तक चलता रहता यदि 'सण्डे' तथा 'इण्डियन एक्सप्रेस' उसका प्रकाश में लाने का साहस और उद्यम न करते।

प्रेस पर अंकुश

किंतु समाचार पत्र-पत्रिकाएं एक अव्यक्त आशंका से आक्रांत हैं। बंगलौर में कुछ दैनिक पत्रों के कार्यालयों का घेराव और उड़ीसा में पत्रकार महापात्र की पत्नी श्रीमती छविरानी पर पहले सामूहिक बलात्कार तथा फिर उनकी हत्या, बाकी प्रेस को सीधी राह पर रखने के लिए यदि काफी नहीं है तो मालिकों की बांह मरोड़ कर पत्रों को ठीक करने की कला नई दिल्ली अच्छी तरह जानती है।

सरकारी मीडिया का दुरूपयोग

प्रचार के सरकारी साधनों, रेडियो तथा टी.वी. का भारी दुरुपयोग, औचित्य की सभी सीमाएं लांघकर, लोकतंत्र के साथ एक भौंड़े मजाक का रूप ले रहा है। अदूरदर्शी शासक यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि यदि उनके प्रचार साधन अपनी विश्वसनीयता खो बैठे तो वे सत्ता पक्ष की डुगडुगी पीटने के घटिया काम को पूरा करने लायक नहीं रहेंगे।

पंगु प्रशासन

केन्द्र में सरकार है, किंतु प्रशासन नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, किंतु उनकी पकड़ नहीं है। सचिवालय काम कर रहा है, किंतु सेवाओं को जैसे लकवा मार गया है। फैसले नहीं किए जा रहे। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री भयभीत हैं, न जाने कब पं. कमलापति त्रिपाठी की तरह रास्ता दिखा दिया जाए। अफसर सहमे हुए हैं, पता

नहीं किस घड़ी कर्त्तव्य पालन के पुरस्कार के रूप में उन्हें सी.बी.आई. के डी.आई.जी. श्री एन.के. सिंह की तरह कारागार और अपमान का शिकार बना दिया जाए।

आपात् स्थिति के दिनों में लांछित मंत्रियों और अफसरों की वापसी ने सारी प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर दिया है। चुनाव में सफलता, जो स्वभावत: अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, शाह आयोग के निष्कर्षों को रद्द नहीं कर सकती, न मारुति के भारी घोटाले को सदाचार का भव्य स्मारक ही बना सकती है।

'आजीवन राष्ट्रपति' तथा 'निर्वाचित न्यायपालिका' की बातें किसी बहके हुए दिमाग की उपज नहीं, एक गहरी साजिश का संकेत है जो नकारात्मक मतों के बल पर प्राप्त सत्ता को हमेशा के लिए हथियाने की दृष्टि से भारतीय गणतंत्र को नष्ट करने पर तुली है। इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए और पूरी तरह पकने से पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए।

दल-बदल को प्रोत्साहन

स्वार्थ-सिद्धि तथा पदलोलुपता पर आधारित दलबदल की अनैतिक प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगाने के बजाए दलगत निष्ठाओं की खरीद का जैसा खुला बाजार गत बारह महीनों में गर्म हुआ है, उससे न केवल राजनेताओं की बची-खुची इज्जत मिट्टी में मिल गई है, बल्कि दल-पद्धति को भी सांघातिक चोट लगी है।

असम में जब विधानसभा का 'ससपेन्डिड एनीमेशन' किया गया था, तब कांग्रेस (आई) की सदस्य संख्या 8 थी। अब यह बढ़कर 56 हो गई है। ध्यान देने की बात यह है कि यह शक्ति वृद्धि उस बीच हुई जब असम की युवा पीढ़ी विदेशी घुसपैठ से असम को बचाने के लिए जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जूझ रही थी। यह संघर्ष आज भी जारी है।

पुलिस-अत्याचार

मुरादाबाद में जनता के एक बड़े भाग से इस भावना का घर कर जाना कि उसे पी.ए.सी. से संरक्षण नहीं मिल सकता, भागलपुर में पुलिसजनों का यह विश्वास कि हवालातियों की आंखें फोड़ कर उन्होंने अपराधों की रोकथाम का अपना कर्तव्य ही पूरा किया है, बागपत में भरे बाजार में पुलिस द्वारा एक महिला को नंगा करने की शर्मनाक घटना और उससे भी ज्यादा कष्टदायक यह तथ्य कि सैकड़ों व्यक्ति उस चीरहरण को टुकुर-टुकुर देखते रहे, यह मात्र प्रशासनिक विफलता या सामाजिक संवेदना के ह्रास की तस्वीर के कुछ नमूने नहीं, चौखटा चरमराने और शीराजा बिखरने के संकट का सबूत है।

इस संकट के नामाभिधान के बारे में भले ही मतभेद हो, इस बारे में कोई विचार भिन्नता नहीं हो सकती कि यह संकट अभूतपूर्व है और किसी एक व्यक्ति का उतरता हुआ जादू, किसी एक दल का बिखरता हुआ ढांचा या टूटता हुआ प्रभाव या प्रशासन का लहूलुहान दबदबा इसका सामना नहीं कर सकता।

आजीवन राष्ट्रपति स्थापित करने का कुत्सित विचार

जो लोग वर्तमान संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति पद्धति की यह सोचकर वकालत कर रहे हैं कि उससे सभी रोगों का रामबाण इलाज हो जाएगा, वे या तो भोले हैं या मक्कार हैं और उनके मक्कार होने की संभावना ही ज्यादा है।

'आजीवन राष्ट्रपति' तथा 'निर्वाचित न्यायपालिका' की बातें किसी बहके हुए दिमाग की उपज नहीं, एक गहरी साजिश का संकेत है जो नकारात्मक मतों के बल पर प्राप्त सत्ता को हमेशा के लिए हथियाने की दृष्टि से भारतीय गणतंत्र को नष्ट करने पर तुली है। इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए और पूरी तरह पकने से पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए।

चुनाव प्रणाली में सुधार

1980 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो जाती है कि जो दल मतदाताओं की बहुसंख्या का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा वह सत्ता में आने में सफल हो गया। गत चुनाव में कांग्रेस (आई) को लोकसभा में 525 स्थानों में से 351 स्थान मिले, किंतु वोटों की दृष्टि से जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, उनमें से केवल 42.57 प्रतिशत ने कांग्रेस (आई) का समर्थन किया।

अल्पसंख्यक वोटों के बल पर बहुसंख्यक स्थान प्राप्त करने की विचित्रता हमारी चुनाव प्रणाली का अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता के बाद किसी चुनाव में कोई ऐसा दल सत्ता में नहीं आया जिसे अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले भारतीयों की बहुसंख्या का समर्थन मिला हो। यहां तक कि 1977 में जनता पार्टी को भी केवल 43.06 प्रतिशत वोट मिले थे।

चुनाव-एक बड़ा जुआ

चुनाव पद्धति कितनी विचित्र है इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया

जा सकता है कि यद्यपि 1971 में कांग्रेस को भी ठीक उतने ही वोट मिले थे जितने 1977 में जनता को प्राप्त हुए थे, फिर भी 43.06 प्रतिशत वोट के बल पर 1971 में कांग्रेस को लोकसभा की 350 सीटें मिली थीं, जबकि जनता को 298 स्थान ही प्राप्त हुए। 1980 में कांग्रेस (आई) 42.57 प्रतिशत वोटों के बल पर 66.86 प्रतिशत स्थान ले गई। जबकि 1977 में जनता को 43.06 प्रतिशत वोटों के आधार पर केवल 56.80 प्रतिशत स्थान ही संसद में मिले। कम वोटों के आधार पर अधिक सीटें मिलने का दृश्य 1952 में ही दोहराया जा रहा है। ब्रिटेन में इस चुनाव पद्धति के आलोचकों ने कहा है कि इसमें चुनाव एक बड़े जुए का रूप धारण कर लेता है।

नई चुनाव-प्रणाली की आवश्यकता

स्पष्ट है कि वर्तमान चुनाव पद्धति दोषपूर्ण है और वह बहुसंख्या की राय को प्रतिबिंबित नहीं करती। राजनीतिक दल सीटों के बल पर यह गर्वोक्ति करते नहीं थकते, कि उन्हें प्रचण्ड बहुमत मिला है, किंतु यह तथ्य बना रहता है कि देश के भीतर उन्हें अल्पमत का ही समर्थन है। संसद या विधानमंडलों में बहुमत के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले तो कर लिए जाते हैं, कानून भी बनाए जाते हैं, संविधान में भी मूलगामी संशोधन कर दिए जाते हैं किंतु इनके पीछे बहुमत का समर्थन नहीं होता। आवश्यक है कि गत चुनाव परिणामों के प्रकाश में हम चुनाव पद्धति में शीघ्र ही कुछ बुनियादी परिवर्तन करें। वर्तमान बहुमत प्रणाली के स्थान पर हमें सूची पद्धति का अवलंबन करना चाहिए जो यूरोप के अधिकांश लोकतंत्रवादी देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। सूची पद्धति मतदाताओं को जाति और संप्रदाय की संकुचित परिधियों से निकाल कर उन्हें दलों की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ देगी। इससे दलों का बिखराव रुकेगा और दलबदल पर अंकुश लगेगा। चुनाव एक जुआ नहीं रहेगा। संसद तथा विधानमण्डलों में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर उन्हें प्राप्त जन-समर्थन के अनुरूप होगा। बहुमत प्रणाली के कुछ लाभ अवश्य हैं। एक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि अपने विकास की ओर अधिक अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है। पश्चिम जर्मनी ने दोनों पद्धतियों की अच्छाईयों का समावेश कर एक मिश्रित प्रणाली का विकास किया है। अच्छा होगा कि हम लोकसभा के लिए सूची पद्धति तथा विधानसभाओं के लिए संयुक्त पद्धति का अवलंबन करें।

चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए निर्मित संयुक्त संसदीय समिति ने 1973 में यह सिफारिश की थी कि भारत में सूची पद्धति लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यह खेद का विषय है कि उस सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस मामले में जनता सरकार का दामन भी बेदाग नहीं है। किंतु जनता सरकार ने कुछ अन्य दूरगामी सुधारों को स्वीकार किया था, जैसे चुनाव का व्यय-भार सरकार वहन करे। यह निश्चय हुआ था कि इस संबंध में कानून बनाने से पहले सरकार विरोधी दलों से परामर्श करेगी। मेरी मांग है कि विशेषज्ञ समिति के गठन में अब और देर न की जाए तथा जनता शासन में स्वीकृत सुझावों को अमल में लाया जाए।

धन-बल के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता

चुनाव में पूंजी का बढ़ता हुआ प्रभाव सदैव ही चिंता का विषय रहा है। किंतु अब तो समस्या ने बड़ा खतरनाक रूप ले लिया है। स्वदेशी धन के साथ विदेशी धन के उपयोग के समाचार भी मिले हैं। चुनाव में धन शक्ति के घातक प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए:-

(1) चुनाव का सारा व्यय-भार राज्य को वहन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर अनुदान दिए जाएं। जो उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल हो उन्हें कानून द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाए।

(2) उम्मीदवार के चुनाव व्यय में उसकी पार्टी द्वारा किए गए खर्च को भी जोड़ा जाए।

(3) राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित की जाए।

(4) समाचार-पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों, पर्चों आदि की अधिकतम व्यवस्था की जाए।

(5) राजनीतिक दलों के आय-व्यय पत्रकों के आडिट की कानूनी व्यवस्था की जाए।

(6) तारकुण्डे समिति ने चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने तथा मताधिकार की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन्हें स्वीकार किया जाए।

जनता सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए रेडियो, टेलीविजन का उपयोग करने की सुविधा देकर एक ऐतिहासिक कार्य किया था। इस सुविधा का विस्तार होना चाहिए। चुनाव प्रसारण के अतिरिक्त राजनीतिक प्रसारणों की एक योजना बननी चाहिए।

दो दिवसीय नवनिर्वाचित विधायक प्रशिक्षण शिविर

सेवा का संकल्प लें, विधायक : राजनाथ सिंह

सूरजकुंड, फरीदाबाद में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। श्री सिंह ने कहा कि सभी विधायक प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प लें। यह सभी विधायकों के लिए जनसेवा, शुचिता व सुराज का अवसर है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन एवं केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने सत्ता का चरित्र बदला है, उसी तरह राज्य में भी इस तरह की शुरुआत हुई है और इसे आगे बढ़ाते हुए सभी विधायकों द्वारा इस तरह का काम किया जाए कि प्रदेश के जन-जन को मान-सम्मान मिले। शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, लोनिवि मंत्री नरबीर सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन, विक्रम सिंह, कृष्ण कुमार, कर्णदेव कंबोज, विनय शहस्त्र, आलोक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व सभी भाजपा विधायकगण मौजूद रहे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी विधायकों को अपनी सरकार का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि वे जाति, वर्ग से ऊपर उठकर प्रदेश की सेवा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि मैं किसी जाति का नेता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सेवा करने का भाव मेरे मन में है।

श्री खट्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें सांझा प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 22 हजार शिकायतें आ चुकी हैं जिनके निवारण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की समस्या न हो इस दिशा में प्रदेश भर के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 12 तक कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा प्राइमरी स्कूल के स्तर पर चिंता जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल का स्तर अच्छा नहीं है जबकि प्राइवेट स्कूल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने विधायकों का बौद्धिक ज्ञान कराया। वहीं, पार्टी प्रभारी श्री अनिल जैन ने पार्टी की छवि जनता में अच्छी रखने के लिए विधायकों को तैयार किया। कोई भी विधायक मीडिया के सामने बिना सोचे समझे कोई बयान ना दे इसके लिए भी सभी को सतर्क किया गया है। ■

योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना

अपने 65 साल के इतिहास में 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 12 पंचवर्षीय और छह सालाना योजनाएं शुरू करने वाला योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाएगा। पिछली 1 जनवरी को योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम बदलकर 'नीति आयोग कर दिया गया। गौरतलब है कि इस संस्था की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग की जगह नई संस्था की स्थापना की घोषणा के कुछ महीनों बाद यह पहल हुई है।

ऐसा होगा नीति आयोग अध्यक्षः प्रधानमंत्री

गवर्निंग काउंसिलः सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

विशेष आमंत्रित सदस्यः विशेषज्ञ (पीएम इन्हें नामित करेंगे)

उपाध्यक्षः प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे

पूर्णकालिक सदस्यः अधिकतम 5

अंशकालिक सदस्यः अधिकतम दो पदेन सदस्य, विश्वविद्यालयों व संस्थानों से बारी के आधार पर होंगे।

पदेन सदस्यः अधिकतम चार केंद्रीय मंत्री

सीईओः केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे

प्रधानमंत्री ने गत स्वतंत्रता दिवस पर योजना आयोग को खत्म करने की घोषणा की थी। उन्होंने सात दिसंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ योजना आयोग की जगह बनने वाली नई संस्था के स्वरूप और शक्तियों के बारे में विचार-विमर्श भी किया। इसके एक माह में नीति आयोग बनाने की घोषणा भी की। नए आयोग का पूरा नाम-नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक व तकनीकी परामर्श देने की होगी। पर नए आयोग के 13 सूत्रीय उद्देश्यों में यह स्पष्ट नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं की मौजूदा व्यवस्था रहेगी या नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं कि नीति आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की भूमिका क्या होगी। पीएम की अध्यक्षता वाले एनडीसी में भी सभी राज्य सदस्य हैं।

'थिंक टैंक के तौर पर काम करने वाला नीति आयोग पीएम और सभी सीएम के लिए विकास का 'राष्ट्रीय एजेंडा' तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीति आयोग जन-केंद्रित, सक्रिय और सहभागी विकास एजेंडा के सिद्धांत पर आधारित है और इससे सहकारी संघवाद की भावना प्रबल होगी। ■

अरविंद पनगढ़िया बने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष

अर्थशास्त्री श्री अरविंद पनगढ़िया को 5 जनवरी को नवगठित 'नीति आयोग' का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही नई संस्था के छह सदस्यों और तीन विशेष आमंत्रितों की भी नियुक्ति कर दी गई है। श्री पनगढ़िया अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री पनगढ़िया के साथ ही अर्थशास्त्री श्री बिबेक देबरॉय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख श्री वीके. सारस्वत को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री सुरेश प्रभु और श्री राधामोहन सिंह को आयोग का पदेन सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्रीमती स्मृति ईरानी और श्री थावर चंद गहलोत को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

62 साल के श्री पनगढ़िया भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वह कोलंबिया विश्वद्यालय में प्रोफेसर हैं। वह एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और कॉलेज पार्क मैरीलैंड के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र केंद्र में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सह-निदेशक रह चुके हैं। ■

झारखंड

दसवें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास ने शपथ ली

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के शासनकाल के दौरान वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठित हुआ। वर्ष 2000 से 2014 तक राज्य में अस्थिरता-अराजकता का बोलबाला रहा, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने संपूर्ण विकास व स्थिरता का नारा दिया जिससे भाजपा-आजसू गठबंधन ने झारखंड में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास ने 28 दिसंबर को रांची में झारखंड के दसवें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके अलावा चार अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस प्रकार मुख्यमंत्री सहित बारह सदस्यीय मंत्रिमंडल में पहले दौर में पांच लोगों ने शपथ ली।

रघुवर मंत्रिमंडल में चार बार से लगातार खूंटी के विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पांचवीं बार रांची से जीत हासिल करने वाले पूर्व स्पीकर श्री सीपी सिंह, पूर्व मंत्री आजसू के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रप्रकाश चौधरी और दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराने वाली डॉ. लुइस मरांडी को जगह दी गई है।

मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव श्री सजल चक्रवर्ती ने राज्यपाल डॉ. सैयद अहमद के आदेश पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद डॉ. सैयद अहमद ने मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और सरकार के अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की बारी-बारी से शपथ दिलाई।

इस विशेष मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह और निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह सहित अन्य नेता शिरकत नहीं कर सके।

समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, श्री सुदर्शन भगत, श्री रामकृपाल यादव, श्री जयंत सिन्हा, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा, आजसू प्रमुख श्री सुदेश कुमार महतो समेत पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, श्री सुशील मोदी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष श्री रवींद्र राय, महामंत्री संगठन श्री राजेंद्र सिंह सहित झारखंड के सभी सांसद और विधायक उपस्थित थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा व श्री हेमंत सोरेन भी समारोह में मौजूद थे।■

भाजपा अजा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

हमारी ध्येय मात्र सत्ता पाना नहीं है अपितु राष्ट्रनिर्माण है : राजनाथ सिंह

व्यक्ति अपने कद से नहीं अपितु अपने कर्मों से बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार ने ही देश में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने का फैसला किया था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरूआत करते हुए 125 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया कि हमें अपने आसपास साफ-सफाई रखना चाहिए। श्री मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों को गाँवों में रहने वालों गरीबों, वंचितों को ध्यान में रखकर आदर्श सांसद ग्राम जैसी योजना का प्रारम्भ किया। हमारी राजनीति का आधार मात्र सत्ता पाना नहीं है अपितु देश बनाना है। यह कहना है देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह का, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 3 जनवरी को देश भर से आये अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत ने अपने मंत्रालय की तरफ से विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए सभा को बताया कि बजट अनुमान 2014 -15 में 6730 करोड़ रुपए की धनराशि के आवंटित किया गया जिसमें से अब तक लगभग 2400 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं जबकि बजट 2013 - 14 में बजट की राशि लगभग 6625 करोड़ थी और 10 सितम्बर, 2013 तक केवल 644 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए थे।

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम ने देश भर से आये प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी हुई एनडीए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए अब तक किए गए विभिन्न कार्यों की भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सराहना करती है। 125 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रखकर श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से निश्चित रूप से देश के गरीब और उपेक्षित समाज सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण और आप सबके अथक परिश्रम से अभी हाल में ही चार राज्यों झारखंड, हरियाणा, जम्मू - कश्मीर और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है जिसके लिए आप सब बधाई और अभिनन्दन के पात्र हैं। हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने और एक लाख रुपए की बीमा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जन - धन योजना की शुरुआत की गई जिसका सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की 895 कॉलोनियों को अधिकृत करने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लगभग 60 लाख से अधिक लोगों को फायदा

होगा।

भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रमुख श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने देश भर से आए सभी प्रतिनिधियों से सदस्यता अभियान के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता को कम से कम 100 सदस्य बनाना होगा साथ ही यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य हों। श्री सहस्त्रबुद्धे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को सक्रिय और विश्वसनीय बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी-बस्तियों, वनवासी क्षेत्रों समेत समाज के सभी वर्गों को सक्रिय सदस्य बनाना होगा।

भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री रामलाल ने देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान पर गहन चर्चा किया तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों को कम से कम 300 नए सदस्य बनाने पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में यदि हम 9 सीटें जीत जायेंगे तो दिल्ली में हमारी सरकार बन जायेगी। 'जहां चुनाव, वहां सरकार,' हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के इस मंत्र को चरितार्थ करने हेतु हमें कड़ी मेहनत करना होगा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री राम माधव, केन्द्रीय राज्यमंत्री विजय साँपला, मध्य प्रदेश के मंत्री लाल सिंह, गुजरात के मंत्री रमन बोहरा समेत भगवत शरण माथुर, रामनाथ कोविन्द, सत्य नारायण जटिया, विजय सोनकर शास्त्री समेत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ■

राजग सरकार का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली में 895 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित होंगी

राजग सरकार ने 29 दिसंबर को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 60 लाख लोगों को नए साल का तोहफा दिया। एक जून, 2014 तक बसाई गई 895 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मंजूरी दे दी है।

विकास परियोजनाओं को मिलेगा लाभ

कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना-प्रसारण व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बताया कि पूर्व संप्रग सरकार ने 31 मार्च, 2002 तक बसाई कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था। लेकिन अब एक जून, 2014 तक की सभी कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। इससे 895 कॉलोनियों में रहने वाले 60 लाख लोगों को फायदा होगा।

इन कॉलोनियों में रहने वालों को दिल्ली के विकास के लिए चलाई जाने वाली तमाम परियोजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन कॉलोनियों में ढांचागत सेवाओं का सही तरीके से विकास हो सकेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इन कॉलोनियों के लोगों को अब होम लोन मिल सकेगा तो जवाब था, 'जाहिर है जब नियमित हो जाएंगे तो लोन भी मिलेगा।' इस फैसले को लागू करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने का फैसला संबंधित एजेंसियां करेंगी।

दिल्ली स्थित कॉलोनियों को लेकर राजग सरकार का यह पिछले कुछ दिनों में दूसरा फैसला है। संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरे संशोधन विधेयक-2014 को पारित करवाया था।

इससे 1200 उन कॉलोनियों को राहत मिली जिन्हें ढहाने का आदेश था। अब इन्हें तीन सालों तक हटाया नहीं जा सकेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद इनमें से 895 कॉलोनियां तो नियमित हो गई हैं। शेष कॉलोनियों के बारे में सरकार आगे फैसला करेगी।

उल्लेखनीय है कि 2012 में दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी 895 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था लेकिन तब इसे केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। साथ ही 2002 से 2014 तक लगभग 300 और कॉलोनियां बसा दी गईं।

ताजा फैसले से इन कॉलोनियों के भी नियमित होने की राह आसान हो गई है। दिल्ली सरकार के पास 1639 कॉलोनियों को नियमित करने का आवेदन है। इनमें 300 कालोनियां और जुड़ जाएंगी। इस तरह से आने वाले दिनों में सरकार को दो हजार कॉलोनियों को नियमित करना पड़ेगा। ■